साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 17 अंक 45 प्रति सोमवार इंदौर, 10 जून से 16 जून 2024 पृष्ठ 8 मूल्य 5/- रुपए

विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी अमेरिका उसकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां व संगठन

चीन रूस उत्तरी कोरिया मिल खत्म करो अमेरिका को

दुनिया के मीडिया को धन बांट अपनी सच्चियां छुपा, रूस, चीन को बदनाम करने का षडयंत्र, पिछले 70 साल से

दुनिया में हथियार बेचने आतंकवाद, पैकेज फूड बेंच बीमारी फैला दवा बेचने, युद्ध युद्ध करवा भारी हथियार बेचने का पिछले 70 सालों से षड्यंत्र कर रहा हैइसकी तकनीकी कंपनियों माइक्रोसॉफ्ट गूगल ने जनता को पूरी दुनिया में उलझा रखा है तो सबसे पहले अमेरिका चीन और दक्षिण कोरिया को इकट्ठे होकर अमेरिका की दुनिया को चल रही दादागिरी को नष्ट करने के लिएआक्रमण करना चाहिएताकि दुनिया की आबादी अगले 100 सालों तक शांति से रह सके।

उसकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक तरफ घटक पैकेज फूड बेचकर बीमारियां बेचती हैंऔर फिर उन बीमारियों को दूर करने के नाम पर सभी दवा टीका उउपकरण उत्पादक कंपनियां अपना माल बेच दुनिया को मोटा बीमारियां बेचती है इसलिए सबसे पहले षड़यंत्रकारी अमेरिका को खत्म होना चाहिए।

रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन की तरफ से कई बार परमाणु युद्ध की धमकी दी गई है। इसके बाद अब अमेरिका परमाणु हथियार बढ़ा सकता है। व्हाइट हाउस के

एक वरिष्ठ सहयोगी ने शुक्रवार को कहा कि रूस, चीन और अन्य विरोधियों से बढ़ते खतरों को रोकने के लिए अमेरिका आने वाले वर्षों में और अधिक रणनीतिक परमाणु हथियारों की तैनाती कर सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के शीर्ष हथियार नियंत्रण अधिकारी प्रणय वड्डी ने अपनी टिप्पणी में कहा कि रूस और चीन पर दबाव डालने के उद्देश्य से एक नीतिगत बदलाव की रूपरेखा तैयार की गई है।

उन्होंने आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन को बताया, 'प्रतिद्वंद्वी शस्त्रागार में बदलाव के अभाव में हम आने वाले वर्षों में एक ऐसे बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां वर्तमान तैनात संख्या में वृद्धि की आवश्यक्ता होगी। अगर राष्ट्रपति यह निर्णय लेते हैं तो हमें इसे क्रियान्वित करनेके लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा।' उन्होंने कहा, 'अगर वह दिन आता है तो इसका परिणाम यह दृढ़ संकल्प होगा कि हमारे विरोधियों को रोकने और अमेरिकी लोगों और हमारे सहयोगियों और साझेदारों की रक्षा के लिए अधिक परमाणु हथियारों की जरूरत है।'

अमेरिका की नीति में बदलाव

अमेरिका वर्तमान में रूस के साथ 2010 की नई एऊँऊ संधि में निर्धारित 1,550 तैनात किए परमाणु हथियारों की सीमा का पालन कर रहा है। लेकिन रूस ने यूक्रेन को अमेरिका के समर्थन के बाद अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया था। इस कदम को अमेरिका ने कानूनी रूप से अमान्य कहा था। वड्डी का बयान अमेरिका की नीति में बड़े बदलाव को दिखाता है। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने इसी ग्रुप को साल भर पहले कहा था कि चीन और रूस का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के रणनीतिक परमाणु हथियारों की तैनाती बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है।

बैंक बन गये पोश डकैती के अड्डे

मोदी ने बैंकों से पूंजीपतियों को लुटाया निर्धनों से लूटा

देश में 2014 मैं मोदी के सत्ता संभालने के बाद अपने पूंजीपति मित्रों अडानी अंबानी टाटा बिरला जेपी, माल्या, जैसे लगभग 200 से ज्यादा खास मित्रों के लगभग 50 से 60 लाख करोड़ जो अलग-अलग बैंकों से लोन लेकर माफ करवा दिए गए। जबकि दूसरी तरफ सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पररिजर्व बैंक में मात्र 16 लाख करोड रुपए बताएं। इन ऋणों से उत्पन्न घाटे की भरपाई करने के लिए रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को अनेकों प्रकार के जनता के धन को हजम करने के लिए पूर्व में जो शर्तें चालू खाता और साख खातों में न्यूनतम शेष की,

बही खाते के पन्ने, जबकि अब अब सारा कंप्यूटर पर होता है, चेक बुक के, डेबिट क्रेडिट कार्ड एटीएम आदि के भारी भरकम शुल्क व शर्तें लागू होती थी। उन शुल्कों व शर्तों को देश के करीबन 200 करोड़ बचत खातों पर लागू कर न केवल लूटने बल्कि खाता बंद करना भी शुरू कर दिया जिससे बैंकों का लाखों करोड़ का लाभ का मार्जिन बढ़ाने के साथ घाटे की भरपाई भी कर ली गई और प्रकार न्यूनतम शेष के नाम पर पिछले 10 सालों में 80 लाख करोड़ बैंक पुणे जनता के हजम कर लिए क्योंकि वह शुल्क था इसलिए लाभ में जोड़ा गया यथार्थ में वह शुल्क जो आम गरीबों की बचत का 100 करोड़ बचत खातों से ही न्यूनतम शेष के नाम पर वसूला और लगभग 100 करोड़ खाता बंद कर दिए गए जो कि मोदी ने कैशलेस नोटबंदी में न्यूनतम शून्य शेष के साथ खुलवाए थे।

(शेष पेज 6 पर)

आम जन को सूचना अधिकार में जानकारी लेने का हक

लोकसभा चुनाव हो चुके, मांगिए मतों की गिनती की एक्सेल शीट

किस प्रकार से फर्जी बड़ा किया जाता है कोई भी जिलाधिकारी आपको गिनती की वर्गीकृत सारणी नहीं देगा पर आप आवेदन लगाइए जिसका प्रारूप करवा रहा हूं।

आज मैं आपको चुनाव की सच्चाई से संबंधित कड़वा सच जानने के लिए हर जिले के जिलाधीश कार्यालय से सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने का तरीका और आवेदन लगाने लिखने कातारिक दे रहा हूं सभी बुद्धिजीवी पत्रकार वकील वह अन्य सामान्य नागरिक अपने-अपने जिलों के जिलाधीश कार्यालय से सूचना के अधिकार में जानकारी मांग कर चुनाव में हुए पूरी जालसाजी भ्रष्टाचार का सच जानने का अवसर दे रहा हूं।

ध्यान रहे सूचना के अधिकार में आवेदन केवल व्यक्तिगत नाम से ही दिया जा सकता है। आप सब ने मतदान किया था देश के नागरिक हैंऔर चुनावों का सच जानने का वैधानिक अधिकार रखते हैं।

जिलाधीश महोदय, जिलाधीश कार्यालय
..... जिले का नाम
सूचना अधिकार में जानकारी प्राप्त करने हेतु
माननीय महोदय,

विनम्र डिवीजन है कि मैं आपके क्षेत्र का प्रदेश व देश का मतदाता हूं मेरे मटका कहां प्रयोग हुआयह जानने का मेरा वैधानिक अधिकार है।

कृपया सत्यापित मुद्रांकित यूआरएल या कंपैक्ट डिस्क लोकसभा चुनाव 2024 में हुए मतगणना की बनाई हुई हर मशीन की मशीन के नंबर के साथ उम्मीदवारों के प्राप्त मतों की बनाई हर तालिका की प्रति के बाद हर कक्ष में सभी मशीनों की बनाई हर कक्ष की कंप्यूटर से बने एक्सेल शीट या वर्गीकृत बनाई सारणी के साथ योग की प्रति फिर सभी कक्षों की हर चक्र की वर्गीकृत लगाई गई कुल सकल योग की प्रतियां के बादहर मशीन हर कक्षा हर चक्रकी बनाई हर उम्मीदवार की हर कक्ष की सभी मशीनों, सभी कक्षों की हर चक्र के सभी चक्रों के कुल सकल महायोग की प्रतियां प्रदान करने का कष्ट करें।

धन्यवाद
आवेदक
हस्ताक्षर
पूरा नाम व पता
मोबाइल नंबर के साथ

आवेदन के साथ में रु. 10 का भारतीय पोस्टल आर्डर के साथ रु. 5 का टिकट लगा अपना पता लिखा लिफाफा संलग्न करें

कहीं पर भीकलेक्टर ऑफिस में गिनती के समय एक्सेल शीट नहीं बनाई गई है और सारे परिणाम मनमानी तरीके से बनाई हुई एक्सेल शीट पर घोषित कर दिए जाते हैं इन हरामखोरों की औकात नहींकी आपको सच-सच सारी जानकारी दे देंफिर भी जो मैं कह रहा थासर फर्जी वाला होता है उसका सच आप भी 20-25 रुपए खर्च करपूरे देश के सभी जिलाधीश कार्यों में आवेदन देकर मालूम कर सकते हैं। वैसे हाल ही में 1 घंटे पहले ही इंदौर कलेक्टर कार्यालय में मैंने एक आवेदन भेजा था। जिसको वहां बैठी मक्कार सूचना का अधिकार आवेदन लेने वाली महिला ने लौटा दियाइसके बाद बोलाकीसुविधा केंद्र में आवेदन दो पर उस हरामखोर ने भी लौटा दिया। वैसे भी इंदौर कलेक्टर कार्यालय यथार्थ में जिले का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी डकैतों का संवैधानिक अड्डा है। जहां सूचना का अधिकार देखते ही हर कार्यालय हर विभाग का हर हर भ्रष्ट निगम में मक्कार कर्मचारी अधिकारी का दिमाग खनक जाता है जैसे सब इनके बाप की जागीर होसरकार जनता से जीएसटी में डेढ़ हजार वस्तुओं में धन लूट और यह हरामखोर इसकी जानकारी भी ना दें। क्योंकि सब डकैतों के बाप की जागीर है।

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

खतरनाक है खेतों से पेड़ों का उजड़ना

साल 2010-11 में दर्ज किये गये पेड़ों में से करीब 11 फीसदी बड़े छायादार पेड़ 2018 तक गायब हो चुके थे. बहुत जगहों पर तो खेतों में मौजूद आधे पेड़ गायब हो चुके हैं.

न तो अब खेतों में कोयल की कूक सुनाई देती है और न ही सावन के झूले पड़ते हैं. यदि फसल को किसी आपदा का ग्रहण लग जाए, तो अतिरिक्त आय का जरिया होने वाले फल भी गायब हैं. अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका 'नेचर सस्टैनबिलिटी' में हाल में प्रकाशित आलेख बताता है कि भारत में खेतों में पेड़ लगाने की परंपरा समाप्त हो रही है.

कृषि-वानिकी का मेलजोल कभी भारत के किसानों की ताकत था. कई पर्व-त्योहार, लोकाचार, गीत-संगीत खेतों में खड़े पेड़ों के इर्द गिर्द रहे हैं. मार्टिन ब्रांट, दिमित्री गोमिंस्की, फ्लोरियन रेनर, अंकित करिरिया, वेंकन्ना बाबू गुथुला, फिलिप सियाइस, जियाओये टोंग?, वेनमिन झांग, धनपाल गोविंदराजुलु, डैनियल ऑर्टिज-गोंजालो और रासमस फेंशोल्टन के बड़े दल ने भारत के विभिन्न हिस्सों में जाकर पाया कि अब खेत किनारे छाया मिलना मुश्किल है.

इसके कई विषम परिणाम खेत झेल रहा है. जब बढ़ता तापमान गंभीर समस्या के रूप में सामने है और सभी जानते हैं कि धरती पर अधिक से अधिक हरियाली की छतरी ही इससे बचाव का जरिया है, ऐसे में यह शोध गंभीर चेतावनी है कि बीते पांच वर्षों में हमारे खेतों से 53 लाख फलदार व छायादार पेड़ गायब हो गये हैं. इनमें नीम, जामुन, महुआ और कटहल जैसे पेड़ प्रमुख हैं. इन शोधकर्ताओं ने भारत के खेतों में मौजूद 60 करोड़ पेड़ों का नक्शा तैयार किया और लगातार दस साल उनकी निगरानी की.

कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अध्ययन के अनुसार, देश में प्रति हेक्टेयर पेड़ों की औसत संख्या 0.6 दर्ज की गयी. इनका सबसे ज्यादा घनत्व उत्तर-पश्चिमी भारत में राजस्थान और दक्षिण-मध्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में दर्ज किया गया है. यहां पेड़ों की मौजूदगी प्रति हेक्टेयर 22 तक दर्ज की गयी. रिपोर्ट बताती है कि खेतों में सबसे अधिक पेड़ उजाड़ना में तेलंगाना और महाराष्ट्र अव्वल रहे हैं.

खेत तो कम होंगे ही, लेकिन पेड़ों का कम होना मानवीय अस्तित्व पर बड़े संकट का आमंत्रण है. आज समय की मांग है कि खेतों के आसपास सामुदायिक वानिकी को विकसित किया जाए, जिससे जमीन की उर्वरा, धरती की कोख का पानी और हरियाली का साया बना रहे.

साल 2010-11 में दर्ज किये गये पेड़ों में से करीब 11 फीसदी बड़े छायादार पेड़ 2018 तक गायब हो चुके थे. बहुत जगहों पर तो खेतों में मौजूद आधे पेड़ गायब हो चुके हैं. यह भी पता चला है कि 2018 से 2022 के बीच करीब 53 लाख पेड़ खेतों से अदृश्य थे, यानी इस दौरान हर किलोमीटर क्षेत्र से औसतन 2.7 पेड़ नदारद मिले. वहीं कुछ क्षेत्रों में तो हर किलोमीटर क्षेत्र से 50 तक पेड़ गायब हो चुके हैं.

यह विचार करना होगा कि आखिर किसान ने अपने खेतों से पेड़ों को उजाड़ा क्यों? किसान भलीभांति यह जानता है कि खेत पर छायादार पेड़ होने का अर्थ है पानी संचयन, पत्ते और पंछियों की बीट से निशुल्क कीमती खाद, मिट्टी के मजबूत पकड़ और सबसे बड़ी बात- खेत में हर समय किसी बड़े-बूढ़े के बने रहने का एहसास. इन पेड़ों पर बसेरा करने वाले पक्षी कीट-पतंगों से फसलों की रक्षा करते थे. फसलों को नुकसान करने वाले कीट सबसे पहले मेड़ के पेड़ पर ही बैठते हैं. उन पेड़ों पर दवाओं को छिड़काव कर दिया जाए, तो फसलों पर छिड़काव करने से बचत हो सकती है. जलावन, फल-फूल से अतिरिक्त आय तो है ही.

फिर भी नीम, महुआ, जामुन, कटहल, खेजड़ी (शमी), बबूल, शीशम, करोई, नारियल आदि जैसे बहुउद्देशीय पेड़ों का काटा जाना, जिनका मुकुट 67 वर्ग मीटर या उससे अधिक था, किसान की किसी बड़ी मजबूरी की तरफ इशारा करता है. यह भी है कि खेती का रकबा तेजी से कम होता जा रहा है. एक तो जमीन का बंटवारा हुआ, फिर लोगों ने व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए खेतों को बेचा.

साल 1970-71 तक देश के आधे किसान सीमांत थे, यानी उनके पास एक हेक्टेयर या उससे कम जमीन थी. साल 2015-16 आते-आते सीमांत किसान बढ़कर 68 प्रतिशत हो गये हैं. अनुमान है कि आज इनकी संख्या 75 फीसदी है. सरकारी आंकड़ा कहता है कि सीमांत किसानों की औसत खेती 0.4 हेक्टेयर से घटकर 0.38 हेक्टेयर रह गयी है. ऐसा ही छोटे, अर्ध मध्यम और मझोले किसान के साथ हुआ.

कम जोत का सीधा असर किसानों की आय पर पड़ा है. अब वह जमीन के छोटे से टुकड़े पर अधिक कमाई चाहता है, तो उसने पहले खेत की चौड़ी मेढ़ को ही तोड़ डाला. इसके चलते वहां लगे पेड़ कटे. उसे लगा कि पेड़ के कारण हल चलाने लायक भूमि और सिकुड़ रही है, तो उसने पेड़ पर कुल्हाड़ी चला दी. इस लकड़ी से उसे तात्कालिक कुछ पैसा भी मिल गया. इस तरह घटती जोत का सीधा असर खेत में खड़े पेड़ों पर पड़ा.

सरकार खेतों में पेड़ लगाने की योजना, सब्सिडी के पोस्टर छापती रही और किसान अपने कम होते रकबे को थोड़ा सा बढ़ाने की फिराक में धरती के शृंगार पेड़ों को उजाड़ता रहा. बड़े स्तर पर धान बोने के चस्के ने भी बड़े पेड़ों को नुकसान पहुंचाया. साथ ही, खेतों में मशीनों के बढ़ते इस्तेमाल ने भी पेड़ों की बलि ली. कई बार भारी मशीनें खेत की पतली पगडंडी से लाने में पेड़ आड़े आते थे, तो तात्कालिक लाभ के लिए उन्हें काट दिया गया. खेत तो कम होंगे ही, लेकिन पेड़ों का कम होना मानवीय अस्तित्व पर बड़े संकट का आमंत्रण है. आज समय की मांग है कि खेतों के आसपास सामुदायिक वानिकी को विकसित किया जाए, जिससे जमीन की उर्वरा, धरती की कोख का पानी और हरियाली का साया बना रहे.

प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में टैक्सियों की चल रही जालसाजी

विभागों में निजी टैक्सियां कर रही कर चोरी वसूल रहीं ज्यादा भुगतान

सरकारी विभागों में किराए की टैक्सियां अधिकांश कर्मचारियों अधिकारियों की, जानकारी देने के बाद भी वरिष्ठ अधिकारी नहीं करते कार्यवाही

पूरे प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में किराये पर टेक्सियां लगाने की प्रक्रिया में जो टेक्सीयां विभागों में बाकायदा निविदायें जारी कर, जिसके अंतर्गत किराए पर उपलब्ध करवाई जारी कारें प्रथमता टैक्सी कोटा में परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होनी चाहिए। उसको चलाने वाले चालक का वाहन चालन अनुज्ञा पत्र व्यवसायिक वाहन चालान की श्रेणी में पंजीकृत होना चाहिए। फिर वाहन का भुगतान किए जाने वाला किराया वाहन की श्रेणी पदस्थ अधिकारी के पद और वेतन मान के अनुकूल अलग-अलग होती है। के अनुकूल ही वाहन को उसे सीमा तक मासिक किराए पर लिया या विभाग में उपयोग किया जा सकता है। पर इन सब नियमों को बलाई तक रख कर प्रदेश के 105 से ज्यादा विभागों के लगभग 10000 से ज्यादा पूरे प्रदेश भर में फैले मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्य सचिव प्रधान सचिवों सभी विभागों के संचालकों प्रमुख अभियंताओं आयुक्तों से संभागीय आयुक्तों जिलाधीश कार्यालयों से उसके अंतर्गत कम कर रहे निगमों पालिकाओं परिषदों खंडो उपखंड विकासखंडों तक मैं संलग्न वाहनों तक में हर महीने लगभग डेढ़ से दो अरब तक का लगभग 1 लाख किराए के वाहनों का भुगतान

सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है। जिसमें लगभग 80% किराए के वहां गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं जो भी किराए के वहां टैक्सी परमिट में स्वीकृत होते हैं उनका हजार रुपए प्रति माह के हिसाब से परिवहन कार्यालय को भी कर का भुगतान करना पड़ता है।

परंतु प्रदेश के लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय जल संसाधन, गृह निर्माण मंडल ग्रामीण यंत्रिकीय, नर्मदा घाटी आदि के सभी संभागों में कार्यपालन यंत्री सहायक यंत्री उप यंत्री से लेकर कर्मचारियों के वाहन, महिला बाल विकास जिलाधीश कार्यालय में संलग्न जिलाधीशों, उप सहायक जिलाधीशों तहसीलदारों के, वाणिज्य कर विभाग आदिम जाति के आयुक्त, संयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्तों वाणिज्य कर अधिकारियों के वाहनों के सभी वृत्तों मैं भी यह फर्जीवाड़ा भरपूर चल रहा है। और जो कारें टैक्सी में लगाए जाते हैं। उन पर मध्य प्रदेश शासन लिखकर वे टैक्सिया इंजीनियरिंग डॉक्टर अधिकारियों को छोड़ने के बाद खुलकर अवैध कार्य शराब धोने गांजा भांग अफीम दरगाह आदि को परिवार में भी खुलकर प्रयोग की जाती है और उसे पर मप्र शासन लिखा होने के कारण अधिकांश समय पुलिस जांच एजेंसियां डर के कारण कोई कार्रवाई नहीं करती। लोक निर्माण विभाग लोक स्वास्थ्य यंत्र की जल संसाधन विभाग के अनेक ऑन कार्यपालन यांत्रियों की टैक्सियां उन्हीं के विभागों में 2 साल 3 साल से ज्यादा पुरानी होने के बाद में भी लगातार अपने ही विभाग में उपयोग कर नई टैक्सियों की भांति दूसरे के नाम से भुगतान ले रही है। पिछले प्रकाशनों में मैंने देवास के जल संसाधन विभाग कार्यपालन यंत्री लखपत सिंह जादौन की खुद की टैक्सी के बारे में छपा था जो हर महीने 26200 का भुगतान जबकि वह 2 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है मासिक किराया ले रही है और सूत्रों के अनुसार वह महीने का हजार रुपए का परिवहन शुल्क भी नहीं जमा कर रही है उसका चालक भी व्यवसायिक वाहन चालन अनुज्ञा पत्र धारी नहीं है।

फिर भी घर भ्रष्ट कार्यपालन यंत्री लखपत सिंह जादौन की इसमें नौकरी खत्म की जा सकती है। मोटा धन लूटकर लूटने के कारण उसके वरिष्ठ अधिकारी चुपचाप रहती हैं। यही हाल इंदौर की सहायक श्रम आयुक्त भट्ट भी अपने कार्यालय में अपने ही वाहन का उपयोग टेक्सी में कर फर्जी ब्लॉक से उसका भुगतान ले रही है इंदौर के लोक निर्माण विभाग मुख्य अभियंता भवन एवं पथ, भवन, 2 अधीक्षण यंत्री 6 कार्यपालन यंत्रियों व सहायक यंत्रियों जो संभाग 1, 2, विद्युत यांत्रिकीय, सेतु, भवन, सड़क डकैती निगम मैं किराए पर ली गई टैक्सियों का भी हाल है। इंदौर के ही स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्यानिकी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, खनन, ग्रामीण, शहरीय विकास पंजीयन आबकारी पुलिस विकास प्राधिकरण नगर निगम अधिकारियों में लगी टैक्सियों का भी है। जो अधिकांश कर्मचारी व अधिकारियों की है और टैक्सियों के नाम पर लाखों रुपए का भुगतान वसूल रही है। जबकि भोपाल के स्वास्थ्य विभाग में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में जो घोटाला पकड़ा गया उसकी एफआईआर कर दी गई इसके पहले टैक्सी घोटाले में आने को विभागों के कर्मचारियों अधिकारियों को निलंबन की बर्खास्तगी की कार्यवाही हो चुकी है।

स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल पर लोकायुक्त में प्रकरण पंजीबद्ध

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत टंडन एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं समस्त प्रकोष्ठों के प्रभारी रहे जे.पी. धनोपिया ने एक संयुक्त पत्रकार वार्ता के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल द्वारा विभाग में प्रायवेट चार पहिया वाहनों के नाम पर वाहनों को अनुबंध कर किराये पर लगाकर आटो और मोटर साईकिल वाहन के गलत तरीके से भुगतान किये जाने संबंधी आरोप लगाये गये थे। उक्त आरोपों में नेताद्वय ने बताया था कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल द्वारा वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबरों में हेरफेर कर चार पहिया वाहनों की जगह आटो एवं मोटर साईकिल वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर पाये गये, जिसका स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा लाखों रूपयों का भुगतान किया गया। नेताद्वय द्वारा सितम्बर माह में पत्रकार वार्ता के माध्यम से लगाये गये आरोपों के आधार पर लोकायुक्त ने उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुये कार्यवाही की तथा पकरण क्र. 0105/ई/24 के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयप्रकाश अस्पताल केंप, भोपाल के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

श्री टंडन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में बढ़े पैमाने पर वाहनों के नाम पर हुये भुगतान और उसमें हुये भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए सूचना के अधिकार कानून के तहत स्वास्थ्य विभाग में लगे किराये के वाहनों की जानकारी एकत्र की गई थी, जिसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टचार सामने आया है। लोकायुक्त ने उक्त प्रकरण को पंजीबद्ध कर स्वास्थ्य विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

लो स्वा यां का जल जीवन मिशन बना लूट का मिशन

प्रमुख अभियंता से सहायक उप यंत्री तक प्रभार देकर प्रभार में

19 वर्ष बाद भी भ्रष्टाचार लूट जालसाजिया छुपाने, सूचना अधिकार की धारा 4 के 25 बिंदुओं की जानकारी साइट पर अपलोड नहीं। खरीदी स्टॉक रख रखाव मरम्मत के नाम भारी भ्रष्टाचार

भारत में विश्व स्वास्थ्य बनाम घातक संगठन के निर्देशों के अनुसार प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी प्रतिदिन सरकार को उपलब्ध करवाना चाहिए। जिसके लिए विश्व बैंक ने भारी मात्रा में कर्ज भी उपलब्ध करवाया और उसी के दम पर पूरे देश में जल जीवन मिशन संचालित किया गया। 22-23 में 45000 करोड़ और 23-24 में 55000 करोड रुपए केंद्र सरकार ने उपलब्ध करवाये। प्रदेश में भी सभी जिलों की निगमों पालिकाओं परिषदों से लेकर 66 हजार गांवों, टोलों, बस्तियों के लिए योजनायें भी बनाई, ठेके भी दिए गए। पर इंदौर भोपाल जैसे महानगरों से लेकर पूरे प्रदेश में गांवों तक पेयजल की समस्याएं अधिकांश स्थानों पर यथावत हैं। बेशक इंदौर जैसे महानगर में हजारों करोड रुपए पेयजल के नाम से खर्च किया जाकर 40% पैसा तक हजम कर लिया जाता है।

आखिर हजम क्यों नहीं होगा इंदौर में ही 30 लाख की आबादी में जहां 4 कार्यपालन यंत्री होने चाहिए। पिछले 40 सालों से एक के भरोसे ही काम चलाया जा रहा है। वह कार्य पालन यंत्री संजीव श्रीवास्तव भी 15 सालों से एक ही स्थान परमैदान में बैठा हुआ है और उसकी इंदौर में लगभग 20 साल से ज्यादा समय से पोस्टिंग है। जिसने द्वितीय और तृतीय चरण में सैकड़ो करोड़ के विस्तारण परिवर्तन समय वृद्धि महंगाई के नाम से हजम किये।

ना ही स्तर के स्तरीय उत्पादकों के स्तरीय एमएस स्टील के आवश्यकता की मोटाई के, उच्च दाब क्षमता के निर्धारित गहराई पर पाइप डालें, ना ही भारतीय स्तरीय कंपनियों की मोटरों पंपों का उपयोग किया गया। जो द्वितीय तृतीय चरण के बनने के बाद जो पूरे शहर को 24 घंटे जलप्रदाय के वादे किए गए थे। पूरा करने की बात तो दूर 40% शहर को पानी ही नहीं पहुंचा और बाकी बचे शहर में जहां नर्मदा जल की आपूर्ति की जा रही है। वहां भी आम नागरिक को 2 दिन में एक बार आधा घंटे पानी देने के बाद में भी रु. 300 महीना वसूल किया जाने के बाद गर्मियों में 30% शहर को वह पानी भी नहीं मिलता। पर बिल वसूली पूरी चाहिए। द्वितीय वा तृतीय चरण की पाइप लाइनों को बिछाते समय ही बड़े-बड़े अरबों रुपए लेकर जालसाजी पूर्ण तरीके से भू और कॉलोनी बहुमंजिला माफियाओं की कॉलोनी में जलापूर्ति कर मोटी कमाई कलेक्टर एडीएम एसडीएम के साथ महापौरो से लेकर पार्षदों तक आयुक्तों से लेकर निगम के मुख्य अभियंता से लेकर अधीक्षण यंत्री सहायक व उप यंत्रियों ने भी मोटी कमाई की। पिछले 15 सालों से लगातार प्रथम द्वितीय तृतीय चरण की इस महानगर में पाइप लाइन फूटती हैं। अधिकांश काम विभाग के कर्मचारियों को ही करना पड़ता है।

परंतु आपातकालीन कार्य दिखाकर मनचाहे टेंडर की स्वीकृति और मनपसंद ठेकेदार को फर्जी भुगतान का खेल सतत चल रहा है। जिसमें सबकी हिस्सेदारी होती है और यही कारण है की संजीव श्रीवास्तव सन 2010 से अकेले ही लूट कर लुटाता है। संभाग आयुक्त जिलाधीश महापौर आयुक्त से लेकर मंत्रियों तक पहुंचाता है। और डटा हुआ है। यही कार्य संभाग क्रमांक 1 नर्मदा जलापूर्ति जलूद में वर्तमान में बैठा कार्यपालन यंत्री पटेल तीनों चरणों के लगे हुए पंपों से लेकर पावर हाउस

मोटरों की मरम्मत रखरखाव से लेकर पानी को साफ करने जिसमें फिटकरी क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर आदि का टनों से उपयोग किया जाता है। और 6.2 पीएच के जल की आपूर्ति इंदौर नगर को करता रहता है।

ग्रामीण संभाग इंदौर में बैठा घोर जालसाज, भ्रष्ट कार्यपालन यंत्री उदिया जो पूर्व में सिंहस्थ के सैकडों करोड़ के भ्रष्टाचार खरीदी का नायक रहा है। इस हरामखोर के भ्रष्टाचारों की जांच करने की अपेक्षा पुरूस्कृत कर इंदौर में पदस्थी दे दी गई पिछले 6 साल से इंदौर में है।

भोपाल के मुख्यालय स्तर के प्रमुख अभियंता सोनगरा का सवाल है। तो वह भी सहायक यंत्री से लेकर कार्यपालन यंत्री तक इसने भी भारी भ्रष्टाचार किए हैं। वर्तमान में सेवानिवृत होने के बाद में भी यह रुपए 50000 करोड़ के बजट में से सैकडों करोड़ की कमाई कर अपने मंत्री और मुख्यमंत्री को पहुंचाने के कारण उसकी जबकि विभाग में अनेकों मुख्य अभियंता हैं। संविदा पर नियुक्ति चल रही है।

धार का प्रभारी कार्यपालन यंत्री हरम सिंह बामनिया जो पूर्व प्रमुख अभियंता गुमान सिंह डामोर 7 हत्याओं का आरोपी और पूर्व के रतलाम झाबुआ सांसद का दूर के रिश्ते में दामाद लगता है। जो घोर बदतमीज होने के साथ सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने और स्टॉक का रिकॉर्ड दिखाने के नाम स्पष्ट लिखकर दे चुका है, कि हमारे यहां स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया जाता। वैसे सारे पूर्व और वर्तमान के प्रमुख अभियंताओं से लेकर कार्यपालन यंत्रियों जो अरबो रुपए का हर साल स्टॉक खरीदते हैं। सब इनके बाप की जागीर है। जो आधा अधूरा स्टॉक खरीद में और बिक्री में मोटा कमीशन भी खाएंगे। पर जानकारी नहीं देंगे। ताकि उनके भ्रष्टाचार पकड़ में नहीं आए। अधिकांश जहां तक मुख्य अभियंता अधीक्षण यंत्रियों का सवाल है। तो इनसे सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी गई थी। मुख्य अभियंता कार्यालय इंदौर में बैठे प्रअ विजय सिंह सोलंकी के कार्यालय ने चार बिंदुओं में से एक बिंदु निरीक्षण कंडिकाओं की जानकारी दी। प्रदेश के सभी कार्य विभागों में प्रशासनिक अधीक्षण यंत्री वह प्रमुख अभियंता को महीने में अपने कार्य क्षेत्र के निरीक्षण हेतु न्यूनतम 10 भ्रमण करने चाहिए। अर्थात 15 महीने में लगभग 150 निरीक्षण किए जाने चाहिए थे जो नहीं किए गए सरकार की गाड़ी का उपयोग अपने व्यक्तिगत उपयोग में लेकर उसे लगभग भरी जाती है और इसीलिए लगभग की कॉपी भी नहीं दी जाती। परंतु बंदे ने सवा साल के कार्यकाल में मात्र 16 निरीक्षण भ्रमण किये और उसकी जांच प्रस्तुति बनाने में भी अधिकांश कार्यपालन यंत्रियों के संभागों में निरीक्षण टीप में खास विवरण जिसमें डीपीआर के अनुसार कार्य हुआ या नहीं हुआ उसका ठेकेदार कौन है, ठेके की कार्य पूरा करने की अवधि ठेका राशि, कितने ऊपर नीचे में गया, डीपी आर में किस कंपनी का पंप लगाया जाएगा। पाइपों की गुणवत्ता निरीक्षण रिपोर्ट आदि गांव की आबादी के हिसाब से आवश्यकता आदि की जानकारी नहीं दी गई। खरगोन में बैठे अधीक्षण यंत्री दलसिंह सूर्यवंशी और इंदौर में बैठे अजय श्रीवास्तव ने सवा साल में कितने निरीक्षण किये और उसकी निरीक्षणों की कॉपी अपने वरिष्ठ कार्यालय को देनी चाहिए वह कापियां भी नहीं दी गई।

यह सारी जानकारियां जो सूचना का अधिकार में मांगी जाती है सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत 25 बिंदुओं की जानकारी में स्वमेव हर कार्यालय को प्रदेश के मुख्यालय से लेकरहर जिले की संभागों को स्वयं अपलोड करनी चाहिए पर सब नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्ट वह जालसाज होने के कारण कोई भी अपनी जानकारियां अपलोड नहीं करता पूरे प्रदेश में संभागीय कार्यालयों से लेकर मुख्यालय तक जो किराए के वाहन पूर्ण टेंडर प्रक्रिया सेलेने के साथ सभी वहां 2 साल से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए और सभी वहां टैक्सी कोटि के होनी चाहिए यहां पर भी अधिकांश वाहन विभागीय कर्मचारियों अधिकारियों के हैं जो टैक्सी कोटा में न होने के साथ हर 3 महीने में परिवहन कार्यालय में उसका मासिक शुल्क जमा नहीं करते हैं आखिर उनकी जांच क्यों नहीं की जाति और किसके अधिकारी कर्मचारी के वहां है उनके ऊपर जांच क्यों नहीं बढ़ाई जाती इसलिए यह लोग बुक और आरसी कार्ड की जानकारी जो स्वयं विभाग की साइट पर अपलोड होनी चाहिए। भ्रष्टाचार जालसाजिया और बंदरबन छुपाने 19 साल गुजर जाने के बाद में भी अपलोड नहीं की जा रही।

मप्र में निजी स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी

शिक्षा को गोरखधंधा बनाने वाले निजी स्कूलों के संचालकों पर सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अब नए तरीके से सरकार इनसे निपटने की तैयारी कर रही है। राज्य शासन ने प्रदेश के सभी निजी स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि वे स्कूल फीस और अन्य विषयों की जानकारी पोर्टल पर आठ जून तक अपलोड कर दें। जबलपुर में कलेक्टर द्वारा की गई कार्रवाई के बाद अब अधिकारियों ने पूरे प्रदेश में इन नियमों को लागू करने की पहल शुरू की है।

स्कूलों क खिलाफ चलेगा अभियान

वहीं, प्रदेश के सभी कलेक्टर को 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर निजी स्कूलों में अनियमितताओं की जांच के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कुछ स्कूलों द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट पाठ्य-पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। इस अभियान में अनियमितताएं चिह्नित होने पर संबंधित प्रकाशक और बुक सेलर्स के खिलाफ नियमानुरूप कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए हैं। विभाग ने सभी कलेक्टरों को जांच के बाद प्रतिवेदन लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त को उपलब्ध कराने के

निर्देश दिए हैं।

स्कूल नहीं कर रहे हैं नियम का पालन

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि राज्य शासन को कुछ निजी स्कूलों द्वारा शासन के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। अनियमितता बरतने की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में सभी कलेक्टर फीस अधिनियम के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराएं।

ये हैं नियम

प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा फीस में वृद्धि एवं इससे जुड़े अन्य विषयों को नियमन करने के लिए मप्र निजी विद्यालय (फीस और संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम-2017 बनाया गया है। इस अधिनियम को 2018 में लागू किया गया था। इसके बाद इस अधिनियम के अधीन मप्र निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम-2020 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार प्राइवेट स्कूलों की फीस और अन्य विषयों पर निर्णय लेकर फीस विनियमन कर सकेगी।

नकली किताबों की जांच करें

आदेश में कहा गया है कि फर्जी और डुप्लीकेट आईएसबीएन पाठ्यपुस्तकों को स्कूलों में चलाया जा रहा है। 30 जून 2024 तक विशेष अभियान चलाकर इसकी जांच करें।

डुप्लीकेट किताब चलाने का खुलासा

जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने 11 निजी स्कूलों की जांच कराकर वहां फर्जी और डुप्लीकेट पुस्तकें चलाने का खुलासा किया था। उन्होंने यह भी पकड़ा कि इन स्कूलों ने 81.30 करोड़ रुपए की फीस ज्यादा वसूल ली। इन स्कूलों पर 22 लाख की पेनाल्टी लगाकर स्कूलों के 20 प्राचार्यों, चेयरमैन, सीईओ, सचिव और अन्य पदाधिकारियों की गिरफ्तार किया गया है।

साप्ताहिक समय माया

महाराणा प्रताप जयंति पर विशेष

अकबर के घमंड को चूर करने वाले महाराणा प्रताप, जिन्होंने कभी नहीं मानी हार

महाराणा प्रताप ने मुगलों के बार-बार हुए हमलों से मेवाड़ की रक्षा की। उन्होंने अपनी आन बान और शान के लिए कभी समझौता नहीं किया। विपरीत परिस्थिति में भी कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि महाराणा प्रताप की वीरता के आगे किसी की भी कहानी टिकती नहीं है। 7 फीट 5 इंच लंबाई, 110 किलो वजन। 81 किलो का भारी-भरकम भाला और छाती पर 72 किलो वजनी कवच। दुश्मन भी जिनके युद्ध-कौशल के कायल थे। जिन्होंने मुगल शासक अकबर का भी घमंड चूर कर दिया। 30 सालों तक लगातार कोशिश के बाद भी अकबर उन्हें बंदी नहीं बना सका। ऐसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप की 9 मई को जयंती है।

महाराणा प्रताप की वीरता की कहानी

महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। राजपूत राजघराने में जन्म लेने वाले प्रताप उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के सबसे बड़े पुत्र थे। वे एक महान पराक्रमी और युद्ध रणनीति कौशल में दक्ष थे। महाराणा प्रताप ने मुगलों के बार-बार हुए हमलों से मेवाड़ की रक्षा की।

उन्होंने अपनी आन, बान और शान के लिए कभी समझौता नहीं किया। विपरीत से विपरीत परिस्थिति ही क्यों ना, कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि महाराणा प्रताप की वीरता के आगे किसी की भी कहानी टिकती नहीं है।

हल्दीघाटी का युद्ध

1576 में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने अकबर की 85 हजार सैनिकों वाली विशाल सेना के सामने अपने 20 हजार सैनिक और सीमित संसाधनों के बल पर स्वतंत्रता के लिए कई वर्षों तक संघर्ष किया। बताते हैं कि ये युद्ध तीन घंटे से अधिक समय तक चला था। इस युद्ध में जख्मी होने के बावजूद महाराणा मुगलों के हाथ नहीं आए।

जब जंगल में जाकर छिप गए थे महाराणा

महाराणा प्रताप कुछ साथियों के साथ जंगल में जाकर छिप गए और यहीं जंगल के कंद-मूल खाकर लड़ते रहे। महाराणा यहीं से फिर से सेना को जमा करने में जुट गए। हालांकि, तब तक एक अनुमान के मुताबिक, मेवाड़ के मारे गए सैनिकों को की संख्या 1,600 तक पहुंच गई थी, जबकि मुगल सेना में 350 घायल सैनिकों के अलावा 3500 से लेकर-7800 सैनिकों की जान चली गई थी। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। आखिरकार, अकबर को महाराण को पकड़ने का ख्याल दिल से निकलना पड़ा। बताते हैं कि महाराणा प्रताप के पास हमेशा 104 किलो वजन वाली दो तलवार रहा करती थीं। महाराण दो तलवार इसलिए साथ रखते थे कि अगर कोई निहत्था दुश्मन मिले तो एक तलवार उसे दे सकें, क्योंकि वे निहत्थे पर वार नहीं करते थे।

26 फीट का नाला एक छलांग में लांघ गया था चेतक

महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी उनकी ही तरह की बहादुर था। महाराणा के साथ उनके घोड़े को हमेशा याद किया जाता है। जब मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लगी गे थी, तब चेतक महाराणा को अपनी पीठ पर लिए 26 फीट के उस नाले को लांघ गया था, जिसे मुगल पार न कर सके। चेतक ने महाराणा को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए।

अकबर की आंखें भी हुई थी नम

महाराणा प्रताप के 11 रानियां थीं, जिनमें मे से अजबदे पंवार मुख्य महारानी थी और उनके 17 पुत्रों में से अमरसिंह महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी और मेवाड़ के 14वें महाराणा बने। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को हुआ था। कहा जाता है कि इस महाराणा की मृत्यु पर अकबर की आंखें भी नम हो गई थीं।

ऐसा 'हाथी' जिसने नहीं की अकबर की गुलामी स्वीकार, तड़प-तड़पकर दे दी अपनी जान

वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के अलावा भी उनकी स्वाधीनता की लड़ाई में एक और पशु था जो चेतक के सामान ही वीर था और उसकी स्वामी भक्ति भी वैसी ही थी, वह था महाराणा प्रताप का गज 'रामप्रसाद'। जब दुश्मनों आक्रांता से युद्ध किया जाता है तो घोड़ों के साथ में हाथियों की भी अहम भूमिका होती थी। वह पैदल सेना को तहस-नहस करके एक मार्ग बनाने में बड़ी भूमिका निभाते थे। इनके द्वन्द्व युद्ध में भी सहायक होते थे। ऐसे ही हाथियों का हल्दीघाटी के युद्ध में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।

• लूणा के बाद रामप्रसाद ने लड़ा युद्धः रामप्रसाद नाम का हाथी मेवाड़ का सर्वश्रेष्ठ हाथी था। इसने युद्ध में मुगल सेना में हड़कंप मचा दिया था। हल्दीघाटी के युद्ध में मेवाड़ के हाथी लूणा का सामना मुगल सेना के हाथी गजमुक्ता से हुआ था। लूणा के महावत को गोली लगने के कारण वह लूणा हाथी बिना

महावत के वापस अपने खेमे में आ गया था।

• युद्ध के दौरान रामप्रसाद को बनाया बंदीः इसके बाद मेवाड़ की ओर से रामप्रसाद को युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया। मुगल सेना ने रामप्रसाद के विरूद्ध रणमदार नाम के हाथी को उतारा। युद्ध में एक समय ऐसा भी आया जब रामप्रसाद मुगलों के हाथी रणमदार पर भरी पड़ रहा था। इसी समय इसके महावत को एक तीर लग गया और वह शहीद हो गया। जिसके बाद भी रामप्रसाद निरंतर मुगल सेना को कुचले रहा। लेकिन मुगल हाथी सेना का सेनापति हुसैन खां अवसर पाकर रामप्रसाद पर चढ़ा गया और उसे नियंत्रित कर के मुगल खेमे में ले गया। वहां इसे बंदी बना लिया गया।

• रामप्रसाद ने त्याग दिया अन्न-जलः हुसैन खां ने इस विस्मित करने वाले जीव को अकबर को उपहार के रूप में दिया। इसे पाकर अकबर अति प्रसन्न हुआ। अकबर के पास पहले ही इसकी प्रसिद्धि पहुंच चुकी थी। उसने इसका नाम बदलकर पीरप्रसाद रख दिया था। अपने स्वामी और स्वदेश से दूर जाना रामप्रसाद के लिए हृदयविदारक था। उसने इस शोक में अन्न-जल का त्याग कर दिया। और युवा अवस्था में ही यह बलशाली और पराक्रमी जीव स्वामी भक्ति की वेदना से मृत्यु को समर्पित हो गया।

महेश नवमी : शुभ मुहूर्त, तिथि एवं योग

हर वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को महेश नवमी मनाई जाती है। यह दिन देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। अतः ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान शिव और मां पार्वती की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। साथ ही भगवान शिव के निमित्त व्रत भी रखा जाता है। यह दिन माहेश्वरी समाज के लिए विशेष होता है। इस दिन ही माहेश्वरी समाज के वंश की उत्पत्ति हुई है। इस शुभ अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा, माहेश्वरी समाज के लोग महेश नवमी पर बाबा की झांकी भी निकालते हैं। धार्मिक मत है कि महेश नवमी पर भगवान शिव की पूजा करने से साधक को मनचाहा वर मिलता है।

शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 15 जून को देर रात 12 बजकर 03 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 16 जून को देर रात 02 बजकर 32 मिनट पर समाप्त होगी। 15 जून को महेश नवमी है। इस दिन ही सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे। इसके अगले दिन यानी 16 जून को गंगा दशहरा है।

एक खडगलसेन राजा थे। प्रजा राजा से प्रसन्न थी। राजा व प्रजा धर्म के कार्यों में संलग्न थे, पर राजा को कोई संतान नहीं होने के कारण राजा दुःखी रहते थे। राजा ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामेष्टि यज्ञ करवाया। ऋषियों-मुनियों ने राजा को वीर व पराक्रमी पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा 20 वर्ष तक उसे उत्तर दिशा में जाने से रोकना। नौवें माह प्रभु कृपा से पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने धूमधाम से नामकरण संस्कार करवाया और उस पुत्र का नाम सुजान कंवर रखा। वह वीर, तेजस्वी व समस्त विद्याओं में शीघ्र ही निपुण हो गया।

एक दिन एक जैन मुनि उस गांव में आए। उनके धर्मोपदेश से कुंवर सुजान बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली और प्रवास के माध्यम से जैन धर्म का प्रचार-प्रसार करने लगे। धीरे-धीरे लोगों की जैन धर्म में आस्था बढ़ने लगी। स्थान-स्थान पर जैन मंदिरों का निर्माण होने लगा।

एक दिन राजकुमार शिकार खेलने वन में गए और अचानक ही राजकुमार उत्तर दिशा की ओर जाने लगे। सैनिकों के मना करने पर भी वे नहीं माने। उत्तर दिशा में सूर्य कुंड के पास ऋषि यज्ञ कर रहे थे। वेद ध्वनि से वातावरण गुंजित हो रहा था। यह देख राजकुमार क्रोधित हुए और बोले- मुझे अंधरे में रखकर उत्तर दिशा में नहीं आने दिया और उन्होंने सभी सैनिकों को भेजकर यज्ञ में विघ्न उत्पन्न किया। इस कारण ऋषियों ने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया और वे सब पत्थरवत हो गए।

राजा ने यह सुनते ही प्राण त्याग दिए। उनकी रानियां सती हो गईं। राजकुमार सुजान की पत्नी चन्द्रावती सभी सैनिकों की पत्नियों को लेकर ऋषियों के पास गईं और क्षमा-याचना करने लगीं। ऋषियों ने कहा कि हमारा श्राप विफल नहीं हो सकता, पर भगवान भोलेनाथ व मां पार्वती की आराधना करो।

सभी ने सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना की और भगवान महेश व मां पार्वती ने अखंड सौभाग्यवती व पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। चन्द्रावती ने सारा वृत्तांत बताया और सबने मिलकर 72 सैनिकों को जीवित करने की प्रार्थना की। महेश भगवान पत्नियों की पूजा से प्रसन्न हुए और सबको जीवनदान दिया।

भगवान शंकर की आज्ञा से ही इस समाज के पूर्वजों ने क्षत्रिय कर्म छोड़कर वैश्य धर्म को अपनाया। इसलिए आज भी माहेश्वरी समाज के नाम से इसे जाना जाता है। समस्त माहेश्वरी समाज इस दिन श्रद्धा व भक्ति से भगवान शिव व मां पार्वती की पूजा-अर्चना करते हैं।

क्यों मनाया जाता है ब्लड डोनर डे

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन की ओर से साल 2004 में पहली बार वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाने के बारे में विचार किया गया. अगले साल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 58 वें महासभा में ब्लड डोनेट करने के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 14 जून को हर साल दुनिया भर में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया. आस्ट्रियन अमेरिकी वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे घोषित किया गया है. लैंडस्टीनर को एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था.

ब्लड डोनर डे का महत्व

कई बीमारियों में बार-बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है. इसलिए बड़ी संख्या में ब्लड डोनर की जरूरत होती है. वर्ल्ड ब्लड डोनर डे दुनिया भर के रक्तदाताओं को जोड़ने का काम करती है. इस अवसर पर रक्तदान के महत्व का प्रचार प्रसार होता है. दुनिया भर में कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं.

विश्व रक्तदाता दिवस का इतिहास

दरअसल, 14 जून 1868 को नोबल प्राइज विजेता कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था. ये वो साइंटिस्ट थे, जिन्हें ब्लड ग्रुप सिस्टम खोजने का श्रेय प्राप्त है। ब्लड ग्रुप का पता लगाने वाले कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन पर ही विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। लैंडस्टीनर को एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज के लिए फिजियोलॉजी के लिए प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

रक्तदान को लेकर वो सबकुछ जो आब जानना चाहते हैं

- एक औसत व्यक्ति के शरीर में 10 यूनिट यानी (5-6 लीटर) रक्त होता है।
- कई बार केवल एक कार एक्सीडेंट (दुर्घटना) में ही, चोटील व्यक्ति को 100 यूनिट तक के रक्त की जरूरत पड़ जाती है।
- एक बार रक्त दान से आप 3 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं।
- भारत में सिर्फ 7 प्रतिशत लोगों का ब्लड ग्रुप 'O नेगेटिव' है।
- O नेगेटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, इसे किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को दिया जा सकता है।
- कोई व्यक्ति 18 से 60 वर्ष की आयु तक रक्त दान कर सकता हैं।
- रक्त दाता का वजन, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर आदि चीजों के सामान्य पाए जाने पर ही डॉक्टर्स या ब्लड डोनेशन टीम के सदस्य आपका ब्लड लेते हैं।
- अगर कभी रक्त दान के बाद आपको चक्कर आना, पसीना आना, वजन कम होना या किसी भी अन्य प्रकार की समस्या लंबे समय तक बनी हुई हो तो आप रक्त दान ना करें।
- पुरुष 3 महीने और महिलाएं 4 महीने के अंतराल में नियमित रक्त दान कर सकती हैं।
- हर कोई रक्त दान नहीं कर सकता। यदि आप स्वस्थ हैं, आपको किसी प्रकार का बुखार या बीमारी नहीं हैं, तो ही आप रक्त दान कर सकते हैं।

दिल और फेफड़ों के लिए खतरनाक है विंटर स्मॉग

सेहत के लिहाज से देखें तो सर्दियों का मौसम काफी अच्छा होता है। इस मौसम में बाजारों में खूब हरी सब्जियां मिलती हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ठंड में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गिरते तापमान की वजह से कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। सर्द मौसम के कारण लोगों में सर्दी-जुकाम, अस्थमा और निमोनिया जैसी बीमारियां अधिक देखने को मिलती है। कुछ मामलों में इनकी गंभीरता हार्ट के खतरे को भी बढ़ा देते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सर्दियों में अपनी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखा जाए।

यूं तो पूरे साल प्रदूषण की समस्या बनी रहती है लेकिन सर्दियों में यह एक बड़ी समस्या बन जाती है। दरअसल, सर्दियों में धुआं कोहर के साथ मिलकर स्मॉग बनाता है।

एक हेल्थ वेबसाइट के मुताबिक, गर्मियों में स्मॉग आसमान में चला जाता है लेकिन सर्दियों में यह हमारे वातावरण में ही रहता है। स्मॉग हमारे हेल्थ पर काफी प्रभाव डालता है। स्मॉग में नाइट्रोजन आक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे जहरीले कण शामिल रहते हैं।

स्मॉग से होने परेशानियां

-बालों का झरना
-इम्यून सिस्टम का कमजोर होना
-आंख, नाक और गले में जलन
-त्वचा से जुड़े रोग
-हाई ब्लड प्रेशर
-ब्रेन स्ट्रोक
-फेफड़ों को नुकसान
-विंटर स्मॉग से बचने के तरीके
-स्मोकिंग न करें
-घर से बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करें
-गुड़ और शहद जैसी चीजें खाएं
-स्मॉग होने पर संभव हो तो घर से बाहर न निकलें या ज्यादा देर बाहर न रहे
-विटामिन सी, अदरक, ओमैगा फैट एसिड और मैग्नीशियम जैसे तत्व वाली चीजें खाएं
-पर्याप्त मात्रा में रोजाना पानी पीएं, खुद को हाइड्रेट रखें
-ठंड दूर करने के लिए लकड़ी सब जलाने से बचें। ●

आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां

तुलसी को खाने से लेकर शरीर पर लगाने तक कई चीजों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। तुलसी की खास बात यह है कि इन पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल, एंटीइंफ्लेमेटरी और एंटीफंगल गुण हैं। ये तीनों ही शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ स्किन की समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं।

आयुर्वेद में जड़ी-बूटियों को कई बीमारियों का रामबाण इलाज माना गया है। कोरोना के बाद से दुनियाभर में घरेलू जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल बढ़ गया है। ऐसे में कुछ हर्बस लंबे समय तक गूगल पर सर्च किए गए। तो, आइए हम आपको ऐसे आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के बारे में बताते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा किया गया है।

दालचीनी

दालचीनी इस साल गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया। बता दें कि दालचीनी का इस्तेमाल वेट लॉस से लेकर स्किन की कई समस्याओं तक में किया जाता है। साथ ही दालचीनी की चाय को डायबिटीज में भी पीने की सलाह दी जाती है।

नीम

नीम तो भारत में कई समस्याओं का रामबाण इलाज माना जाता है। नीम की पत्तियों को पीस कर पीने से जहां पेट के कीड़े मर जाते हैं वहीं, इन पत्तियों का सेवन शरीर पर दाने और खुजली को कम करने में मदद करता है। साथ ही इन पत्तियों को पीस कर आप अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं।

माचा ग्रीन टी की पत्तियां

माचा ग्रीन टी या कहें कि ग्रीन टी की पत्तियां, वेट लॉस के लिए हमेशा से ही कारगर माने गए हैं। दरअसल, माचा ग्रीन टी पीने से शरीर डिटॉक्स होता है। वहीं, इसका एंटीबैक्टीरियल गुण स्किन की कई समस्याओं को दूर करने में मदद करता है।

हल्दी

हल्दी को हमेशा से कई बीमारियों का रामबाण इलाज माना जाता रहा है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीइंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के साथ शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं। इसे आप सर्दी-जुकाम और हड्डियों की समस्याओं से बचने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

सौंफ

सौंफ को यूं तो, माउथ फ्रेशनर माना जाता है लेकिन, ये मुंह की बदबू और पेट की कई समस्याओं को दूर करने में इस्तेमाल किया जाता है। आप वजन घटाने के लिए सौंफ का पानी पी सकते हैं, तो आप मतली में सौंफ चबा भी सकते हैं।

कैमोमाइल

कैमोमाइल को लोग काढ़ा और चाय जैसी कई चीजों में इस्तेमाल करते हैं। इसकी खास बात यह है कि एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर है जो कि स्ट्रेस कम करता है और एंग्जायटी में कमी लाता है। इस तरह ये शरीर को स्ट्रेस बनाता है।

शहद

शहद एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है। ये दोनों ही चीजें वेट लॉस के साथ स्किन की कई समस्याओं को कम करने में कारगर हैं। आप इसे पानी में मिला कर सुबह खाली पेट ले सकते हैं। साथ ही एक्ने की समस्या में आप इसे अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं।

सहजन

मोरिंगा या कहें कि सहजन को पीस कर या इनकी पत्तियों को पीस कर इसका सेवन करना डायबिटीज की बीमारी में कारगर तरीके से काम करता है। साथ ही वेट लॉस के लिए आप मोरिंगा टीन का भी सेवन कर सकते हैं। ●

गिलोय

गिलोय को लोग कई समस्याओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। गिलोय में एंटीबैक्टीरियल और एंटीइंफ्लेमेटरी गुण हैं जो कि हड्डियों में दर्द और सूजन की समस्या को कम कर सकते हैं। इसके अलावा ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है जिसे सर्दी-जुकाम में इस्तेमाल किया जाता रहा है।

साप्ताहिक समय माया

बैंक बन गये पोश डकैती के अड्डे

नाइंसाफी न्यूनतम बैलेंस न रखने पर सरकारी-निजी बैंकों की तानाशाही

ये मनमानी है... बचत खाते पर क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट से तिगुनी पेनाल्टी वसूल रहे बैंक

गुरुदत्त तिवारी | मुंबई

क्या बैंक खातों में 'न्यूनतम बैलेंस' न रखना क्रेडिट कार्ड 'डिफॉल्ट' से भी बड़ा अपराध है? देश के बैंक तो यही मनमानी कर रहे हैं। वे क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट पर सालाना 40% पेनल्टी लगाते हैं, लेकिन 'बचत खातों' में न्यूनतम बैलेंस न रखने वालों पर सालाना 103% पेनल्टी लगा रहे हैं। फाइनेंशियल व्हिसिल ब्लोअर सुचेता दलाल के 'मनीलाइफ फाउंडेशन' और आईआईटी बॉम्बे के एक्सपर्ट्स ने यह खुलासा किया है। शेष पेज 07 पर

बैलेंस कम होने पर स्लैब का फंडा समझिए

रिजर्व बैंक ने शॉर्टफॉल के लिए 1000 रुपए तक के तीन स्लैब तय किए हैं। रिजर्व बैंक की मंशा है कि ज्यादा 'शॉर्टफॉल' होने पर ग्राहक को बहुत ज्यादा पेनाल्टी न भुगतनी पड़े, लेकिन बैंक मनमानी कर रहे हैं।

कायदे से यह होना चाहिए...

स्लैब	शॉर्टफॉल (रु.)	औसत	तय पेनाल्टी	प्रतिशत
1	1-500	250	100	40%
2	501-750	625	160	25.6%
3	751-1000	875	200	22.9%

(तीनों का औसत 32.1% होता है। कोई बैंक तिमाही आधार पर न्यूनतम बैलेंस पेनाल्टी लगाता है तो यह 10.7% होना चाहिए। लेकिन बैंक 3.22 गुना तक पेनाल्टी वसूल रहे हैं।)

जैकेट का शेष...

ये मनमानी है... बचत खाते पर क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट...

इन विशेषज्ञों ने 25 सरकारी और निजी बैंकों के न्यूनतम बैलेंस न रखने पर पेनाल्टी का अध्ययन किया। रिपोर्ट के अनुसार, शॉर्टफॉल (न्यूनतम बैलेंस से कम राशि) पर बैंक सालाना 103% पेनाल्टी वसूल रहे हैं। नियम यह है कि शॉर्टफॉल राशि को 3 स्लैब में प्रतिशत के आधार पर पेनाल्टी लगाई जानी चाहिए। स्लैब बढ़ने पर प्रतिशत घटना चाहिए।

औसतन 8.6% मासिक, 103% सालाना वसूली

बैंक	मासिक	सालाना
यूनियन	5%	60%
आईडीबीआई	5%	60%
केनरा	5%	60%
बैंक ऑफ बड़ौदा	6%	72%
महाराष्ट्र	6%	72%
एचडीएफसी	07%	84%
आईसीआईसीआई	07%	84%
कोटक	07%	84%
एक्सिस	07%	84%
बैंक ऑफ इंडिया	11%	121%
आईओबी	11%	121%
फेडरल	8%	96%
पीएनबी	8%	96%
सेंट्रल	8%	96%

• रिपोर्ट कहती है कि ...
सबसे ज्यादा शुल्क ...
'औसत चार्ज' सरका...
• तकनीकी कारणों से ...
पास बैंक ले रहा है। ...
स्टैंडर्ड चार्टर्ड व इंडि...
फाइनेंशियल ट्रांजेक्श...
पिन जनरेशन पर ...
• आईडीएफसी फर्स्ट ...
शुल्क है।
• एयू स्मॉल फाइनेंस ...
इसके ऑनलाइन ...
लगने वाले शुल्क से ...
से बचने के लिए ...
• एसबीआई के अति...
बैलेंस पर कोई शुल्क ...
• केनरा और एक्सिस ...
सबसे ज्यादा शुल्क ...
पिन जनरेशन, एसए...
है।
• एक्सिस बैंक 'न्यून...
लेता है। बैंक खुद के ...
लेनदेन' सबसे ज्याद...
25 में से 16 बै...
पीछे नहीं : • 25 में ...
अगली 12 ने प्रतिश...
• 9 बैंकों में स्लैब ...
सालाना) था। • 14 ...
प्रतिशत में न लेकर ...
अलग-अलग स्लैब ...
प्रतिशत में थी। नियम ...
चाहिए।

पेज 1 का शेष

उसके साथ में बेंकों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो बैंक है भारत में या विदेश में काम कर रही थीं। उनके तरीके से अनेकों प्रकार की छल कपटपूर्ण वसूली के षड्यंत्र कर बैंकों में बचत खातों में 4% ब्याज देने के बदले में जो काम मोदी के पहले बैंक निशुल्क करते थे बात मोदी के आने के बाद बैंकों ने अपने घाटे को पूरा करने के लिए उन सबका भारी शुल्क वसूल करना शुरू कर दिया जो सरकारी स्टेट बैंक में चेक बाउंस होने पर 25-50 रुपए लगते थे उनका सीधा रु.500 न्यूनतम शेष के नाम पर भी भारी शुल्क वसूलना ज्यादा लेन-देन करने पर उसे पर भी शुल्क वसूलना एटीएम कार्ड के चार से ज्यादा जमा करने या निकालने पर पांचवी पर 18% जीएसटी ठोका तो एक तरफ बैंकों ने पांचवें लेन देन के पर 18% सरकार को जीएसटी दी तो 175 रु. प्रति सौदे पर वसूली करना शुरू कर दिया।

जो यथार्थ में आम गरीब व्यक्तियों पर जिनकी आए न्यूनतम 8 से रु. 10000 महीने थी उनको भी इसका शिकार होना पड़ा और बदले में उसे लाभ को न केवल मोदी ने अपने उपयोग में लेने के साथ-साथ अपने पूंजीपति मित्रों को और इससे प्रेरित होकर कर्ज माफ करने के बाद में भी खुलकर कर्ज बांटना शुरू कर दिए। दूसरी तरफ भारत के स्टेट बैंक से लेकर सभी सरकारी बैंकों के साथ निजी क्षेत्र के बैंकों में भी लगभग 100 करोड़ से ज्यादा बचत खातों में पड़े हुए लगभग 70 से 80 लाख करोड रुपए जिम खातेदारियों की मृत्यु स्थानांतरण स्थान परिवर्तन या अन्य अनेकों कर्म के कारण लेनदेन नहीं हो रहा है उन उदासीन खातों में सेभी हर साल लाखों करोड़ पिछले 10 साल में बैंकों ने अपने लाभ में दिखाकर हन करने के साथ-साथ वहां बैठे कर्मचारियों अधिकारियों नेभी उन खातों में फर्जी लेनदेन कर पैसा हजम कर लिया अब जब वर्तमान में अधिकांश बैंक संगणीकृत हो चुके हैं। तो खातों में भी खातेबही के पन्ने का शुल्क लेना कहां तक उचित है? इसे सरकार को भारतीय बैंकों के बैंक रिजर्व बैंक को तत्काल निर्देश देकर तत्काल बंद करना चाहिए दूसरी तरफ वर्तमान में बैंकों में संगणीकरण के कारण 30% कर्मचारी ही रह गए हैं। तो उससे भी स्थापना खर्च घटने के कारण मोटा फायदा बैंकों को हो रहा है। दूसरी तरफ मोदी ने अपने आने के बाद अधिकांश बैंकों मैं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से लेकर नीचे बड़े शहरों की बड़ी शाखाओं में मलाई वाली पदों पर गुजरातियों का स्टाफ बैठा के लूट, डकैती ऑनलाइन जालसाजी के अड्डों को खुली शह दे दी। वर्तमान में अधिकांश सरकारी बैंकों में बैठा हुआ स्टाफ जिसमें खासतौर से स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया और उसकी सारी शाखाएं जो देश भर में फैली हुई है यंत्रीकरण के साथ-साथ वहां बैठा हुआ स्टाफ घर बदतमीज मक्कार और कामचोर होने के साथ वहां पर आने वाली गरीब खाताधारियों से बदतमीजी तो करता ही है उनके खातों में सेंड लगाने और खातों को बंद करनेका षड्यंत्र भी करता है।

मोदी ने रिजर्व बैंक से लेकर अन्य सभी सरकारी बैंकों को लूटने वह आम गरीब लोगों को लूटने के लिए सरकारी व सभी गैर सरकारी बैंकों को विभिन्न प्रकार के शुल्क लगाकर जबकि सारी बैंक के जनता की बचत खातों के धन पर न्यूनतम 4% ब्याज देकर उसे पर कई गुना ज्यादा ब्याज कमाने के साथ बड़े-बड़े उद्योगों और ठेकों में हजारों करोड़ का ऋण बांट कर ही चलाई जाती है तो सरकार को चाहिए कि देश में 125 करोड़ जनता में बचतों को प्रोत्साहित करने बचत खातों में न केवल न्यूनतम शेष पर कम से कम मासिक 10 लेनदेन पर किसी भी प्रकार का कोई भी सेवा शुल्क के नाम पर वसूली करना बंद करें वैसे भी इस प्रकार की केबल 60% खाते ही है जहां पर निर्धन लोग अपनी बचत जमा करके उनमें ज्यादा लेनदेन करने की तो दूर महीनों तक धन और समय अभाव में जमा और आहरन नहीं कर पाते हैं। अकेले नोटबंदी के समय पूरे देश भर में स्टेट बैंक ऑफ़ सरकारी बैंकों में लगभग 50 करोड़ से ज्यादा स्वयं सरकार के कहने पर शून्य शेष पर ग्रामीण व निर्धन शहरियों के खाते खुलवाए गए। परंतु 6 से 12 महीना के अंदर ही बैंकों ने उसमें जमा लगभग 40 लाख करोड रुपए हजम करके सारे खाता बंद कर दिए और यह चुकी सेवा संघ के रूप में वसूला गया था उसे लाभ में दिखाकर अपने मित्रों के लाखों करोड़ों माफ करने केघाटे को पूरा कर लिया गया जो की जनता के साथ में इस गुजराती जाल साज डकैत की 50 करोड लोगों के साथ सरकारी बैंकों की कानूनी शुल्क डकैती का हिस्सा थी। इसके संबंध में भास्कर ने भी एक लेख प्रकाशित किया है जो अधूरा था उसमें बहुत सारी जानकारियां परिलक्षित ना होने के कारण उपरोक्त लेख लिखा गया साथ में भास्कर खबर लेख भी नीचे दिया जा रहा है।

बारूद के ढेर पर... राजवाड़ा, सराफा, रानीपुरा और कपड़ा बाजार

शहर के ज्यादातर बाजारों में दमकल वाहन निकलने तक की जगह नहीं है

राजवाड़ा, सराफा, जेल रोड, रानीपुरा, शकर बाजार, कपड़ा बाजार, सीतलामाता बाजार जैसे इंदौर के दर्जनों ऐसे क्षेत्र हैं, जो बारूद के ढेर पर खड़े हैं। इन बाजारों की तंग गलियों में चार पहिया वाहन तो दूर दोपहिया से गुजरना भी मुश्किल है। लापरवाही का आलम यह है कि दुकानदार पहले से तंग इन गलियों में दुकानों के आगे अतिक्रमण कर लेते हैं और निगम के जिम्मेदारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती।

दिन के वक्त इन सभी पुराने बाजारों में खरीदारों की जबर्दस्त भीड़ रहती है जबकि रात होते ही ये खाने-पीने के ठियों में बदल जाते हैं। आग लगने की स्थिति में इन बाजारों की तंग गलियों में इतनी जगह तक नहीं होती कि दमकलें निकल सकें।

ऐसा भी नहीं कि शहर के जिम्मेदारों को इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सभी आंख मूंदकर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बदतर स्थिति राजवाड़ा से सटे सराफा, पीपली बाजार, सीतलामाता बाजार, रानीपुरा जैसे सघन बाजारों के हैं। किसी समय ये बाजार मुख्य सड़क पर ही लगते थे, लेकिन समय की मांग के चलते इन बाजारों ने अपने आपको आसपास की गलियों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। स्थिति यह है कि शहर के ज्यादातर बाजारों के आसपास की गलियों में पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती। टीम ने शहर के बाजारों का अवलोकन किया तो चौंकाने वाली वास्तविकता सामने आई।

शहर के किसी भी बड़े बाजार में आग लगने की स्थिति से निपटने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये बाजार पूरी तरह से अग्निशमन विभाग के भरोसे हैं। इन बाजारों से फायर ब्रिगेड कार्यालय भले ही ज्यादा दूर न हो, लेकिन सघन बाजारों के चलते मौके पर पहुंचना दमकलों के लिए आसान नहीं। दमकल बाजारों की मुख्य सड़क तक पहुंच भी जाएं तो गलियों में पहुंचना इनके लिए आसान नहीं।

राजवाड़ा के आसपास हैं 13 बाजार, तंग गलियां हैं इनकी पहचान

राजवाड़ा से सटकर 13 बडे बाजार हैं। इनमें निहालपुरा, सराफा, पीपली बाजार, धान गली, बर्तन बाजार, मारोठिया, बोहरा बाजार, शकर बाजार, सीतलामाता बाजार, क्लाथ मार्केट, सांठा बाजार, खजूरी बाजार, मल्हारगंज शामिल हैं। इन सभी बाजारों की पहचान तंग गलियों से है। इन बाजारों में कहीं कपड़े का व्यापार होता है तो कहीं खाने-पीने की चीजों का। ज्यादातर बाजारों में तंग गलियां हैं। आग लगने की स्थिति में इनमें दमकलें पहुंच ही नहीं सकतीं। यह प्रदेश के सबसे बड़े मोबाइल मार्केट में से एक है। सैकड़ों की संख्या में दुकानें हैं। जेल रोड के आसपास की तंग गलियों से पैदल गुजरना भी मुश्किल है। ऐसे में कभी आग लग जाए तो स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा।

रानीपुरा में कठिन है फायर ब्रिगेड का पहुंचना

रानीपुरा क्षेत्र में होजयरी, कास्मेटिक, घरेलू सफाई, खिलौने, चूड़ी जैसे कई उत्पादों की दुकानें हैं। यहां पर तंग छोटी-छोटी गलियों में दुकानें बनी हैं। ऐसे में आग लगने पर इन गलियों में फायर ब्रिगेड का पहुंचना भी मुश्किल होता है। यहां की अधिकांश दुकानों में अग्निशमन उपकरण तक नहीं हैं। ऐसे में आग लगने पर उस पर तत्काल नियंत्रण पाना आसान नहीं है। गौरतलब है कि सात साल पहले रानीपुरा में पटाखा गोदाम में आग लगने के कारण आठ लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद इस क्षेत्र में पटाखों का संग्रहण जरूर प्रतिबंधित किया गया है। कई इमारतों में तलघर में गोदाम व दुकानें भी नियमों को ताक में रखकर बनाई गई हैं।

सभी सरकारी व निजी शिक्षण व कोचिंग संस्थान लूट वसूली के अड्डे

भाजपाई सरकारें नहीं चाहती निर्धन बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें

सभी उच्च प्रवेश व शैक्षिक परीक्षाओं के माफियाओं द्वारा पेपर लीक से मोटी कमाई और अपने बच्चों को पास करवाने का षड्यंत्र

पूरे देश व प्रदेशों में जब-जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया। तब तक उन्होंने मोटी कमाई करने जो सामाजिक जीवन में सबसे बड़ी मनुष्य जीवन को पूरा करने के लिए आवश्यकताओं का इसमें शिक्षा स्वास्थ्य सड़कें बिजली पानी आदि जो सरकारों को जनता से भारी भरकम कर वसूलकर मुफ्त में उपलब्ध करवानी चाहिए थी। से मोटी कमाई करने व्यवसायी करण कर निजीकरण करने का इन भूखेरे जालसाजों ने षड्यंत्र किये। 1987-88 में प्रदेश में भाजपा की मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा व कैलाश जोशी की सरकार बनी थी। उसी समय से प्रदेश के शिक्षा और स्वास्थ्य का तेजी से व्यवसायीकरण से लूट डकैती जालसाजियों का प्रारंभ हो गया था। फिर भी सन 2000 के पहले तक भारतीय जनता पार्टी जो शिक्षित स्वाभिमानी बुद्धिजीवी वर्ग के नेताओं के कारण अनुशासन और नैतिकता को सर्वोच्च मानती थी। सन 2000 के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों और पूंजीपतियों के मोटे कमीशन व इशारे पर स्व.प्रमोद महाजन, अरूण शौरी जैसे घोर स्वार्थी मक्कार लालची नेताओं के कारण न केवल देश के सरकारी मानव निर्मित व सार्वजनिक प्राकृतिक संपत्तियों, संस्थाओं को लूटने बैचने गिरवी करने पर तुल उन्होनें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, बिजली पानी सबका व्यवसाई करण करके शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में नोनीहालों शिशु घरों से लेकर प्राथमिक माध्यमिक उच्चतरसाले शिक्षा महाविद्याल य साधारण डिग्री कोर्सों से उच्च इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन कंप्यूटर, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, चिकित्सा शिक्षण संस्थानों से भेषज तब के सभी पाठ्यक्रमों के महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालयों तक को जनता को हर कदम कदम पर प्रवेश परीक्षा से लेकर शिक्षण संस्थानों तक में अध्ययन करने से लेकर प्रायोगिक व लिखित परीक्षाओं के लिए लूटने जालसाजी करनेकी खुली छूट दे दी। जैसा की सन 2000 में मैंने लिखा था यह सारी दुकानशिक्षण संस्थानों केनिर्धारित मापदंडों को पूरा करने की तो दूर उनके पास ना तो शिक्षण संस्थान की आवश्यकता के अनुकूल भवन खेल मैदान प्रयोगशाला पुस्तकालय विद्यार्थियों को बैठने के लिए कक्ष ही नहीं होते तो शिक्षण कार्य के लिए उच्च शिक्षित, विषयों में पारंगत शिक्षकों प्राध्यापकों अधिष्ठाता तो बहुत दूर की कौड़ी है। परंतु विद्यार्थियों से शिक्षण के नाम पर प्रवेश, आरक्षित निधि, पुस्तकालय, भवन, प्रयोगशाला, खेल मैदान, योग, पीटी, वाहन शुल्क मोती शिक्षक सूची के साथ में भी वसूला जाता है जबकि थॉट में 90% निजी शिक्षण संस्थान केवल प्रमाण पत्र, अंक सूचियां, डिग्री डिप्लोमा बांटने की चाय पान की दुकानों गुमटियों से ज्यादा कुछ नहीं है। अधिकांश निजी शिक्षण संस्थानों छात्रावासों में जालसाज डकैत, अय्याश, लंपट, नेताओं अधिकारियों और पूंजीपतियों का धन निवेशित होता है। इसलिए 20-25 सालों सेप्रदेश में इंदौर और भोपाल दो उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ कोचिंग से शिक्षण के भी बड़े केंद्र बन चुके हैं। जहां लगभग 20000 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षण व कोचिंग के लिए आते हैं। राजस्थान का कोटा जो देश में माना हुआ कोचिंग संस्थानों का अड्डा होने के साथ लूट डकैती के लिये विद्यार्थियों पर भारी भावनात्मक और शैक्षिक दबाव बनाने के कारण आत्महत्या का भीदेश का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। सारे जालसाज कोचिंग संस्थान अपने यहां के छात्रों की अधिकतम 100% तक की उपलब्धियां दिखाने के लिए यही कोचिंग संस्थान देश के मानव संसाधन के अंतर्गत काम करने वाले विभिन्न चिकित्सा इंजीनियरिंग व आनंद प्रकार की प्रवेश परीक्षा में परीक्षा का प्रबंध करने वालों से ही मोटा पैसा देकर पेपर खरीद कर छात्रों से मोटा पैसा लेकर उन्हें उपलब्ध करवा कर पूरा प्रश्न पत्र हल करवा देते हैं। जबकि छात्रों से इस बारे में पूछताछ करने पर मालूम पड़ा अधिकांश शिक्षण संस्थान बड़े-बड़े एयर कंडीशन हाल में छात्रों को बैठा कर पूरी कोचिंग ऑनलाइन या रिकॉर्डेड मॉनिटर स्क्रीन पर देते हैं। इस प्रकार उनके पास कोचिंग देने वाले शिक्षक ही नहीं होते परंतु फीस लाखों में वसूल की जाती है। आखिर सरकार को उन्हें रोकना चाहिए और अभी हाल ही में एनटीए में पेपर लीक कांड चल ही रहा है। इसमें बड़े-बड़े औद्योगिक घराने पूंजीपति और शिक्षकों का पूरे देश में दबदबा बना चुका है।

नीट रिजल्ट फिर से जारी होगा या परीक्षा दोबारा होगी

मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के रिजल्ट में कथित गड़बड़ी के बाद मचे हंगामे और सीबीआई जांच की मांग के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने ग्रेस मार्क्स मामले की जांच के लिए एक चार सदस्यीय कमिटी बनाई है। यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन की अगुवाई में यह कमिटी एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। एनटीए ने कहा

कि स्टूडेंट्स को ग्रेस अंक देने से नतीजों या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में कोई फर्क नहीं पड़ा है। एनटीए ने पेपर लीक होने के आरोपों को भी खारिज कर दिया। एनटीए डीजी सुबोध कुमार सिंह ने कहा, यह मसला सिर्फ 1600 स्टूडेंट्स का मसला है। पेपर 23 लाख से ज्यादा बच्चों ने दिया था। 4750 सेंटर की बजाय सिर्फ 6 सेंटर का मामला है। कमिटी इन करीब 1600 स्टूडेंट्स को दिए गए ग्रेस मार्क्स व टाइम लॉस मामले की जांच करेगी। जरूरत पड़ेगी तो इनका रिजल्ट संशोधित किया जा सकता है। इससे नीट रिजल्ट के बाद होने वाली एमबीबीएस व बीडीएस समेत विभिन्न मेडिकल कोर्सेज की एडमिशन प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कमिटी की जो सिफारिशें आएंगी, हम फैसला लेंगे।

एनटीए महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने उच्च शिक्षा सचिव के. संजय मूर्ति और सूचना प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीट मामले में स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि जिन केंद्रों पर छात्रों ने समस्या का सामना किया उनमें से दो केंद्र छत्तीसगढ़ में बालोद और दंतेवाड़ा में हैं, जबकि एक केंद्र बहादुरगढ़ में, एक मेघालय में, एक सूरत में और एक चंडीगढ़ में है। पेपर लीक के आरोपों पर उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर जो पेपर आया, वह पेपर शुरू होने के बाद आया था। हम भविष्य में अपने प्रोटोकॉल व स्टैंडर्ड को और मजबूत बनाएंगे ताकि फिर से इस तरह की गलती फिर से नहीं हो।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुबोध कुमार सिंह ने कहा, टॉइम लॉस होने के मामले पर हमारी समिति ने बैठक की थी और उन्होंने केंद्रों और सीसीटीवी के सभी विवरणों का अध्ययन किया था। उन्हें पता चला कि कुछ केंद्रों पर समय की बर्बादी हुई और छात्रों को इसके लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। समिति ने सोचा कि वे शिकायतों को दूर कर सकते हैं और छात्रों को मुआवजा दे सकते हैं। इसलिए कुछ छात्रों के अंक ग्रेस मार्क्स देकर बढ़ा दिए गए। इसके कारण, कुछ छात्रों की चिंताएं सामने आईं क्योंकि कुछ उम्मीदवारों को 718 और 719 अंक मिले और 6 उम्मीदवार टॉपर बन गए। हमने सभी चीजों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया है और परिणाम जारी किए। 4750 केंद्रों में से, यह समस्या 6 केंद्रों तक सीमित थी। और 23 लाख छात्रों में से केवल 1600 छात्रों को इस समस्या का सामना करना पड़ा। छह केंद्रों पर प्रश्नपत्रों के गलत वितरण के कारण ऐसा हुआ। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि उन्हें कम समय मिला। हमने उच्च न्यायालय में जवाब दिया है कि हमने विशेषज्ञों की एक शिकायत निवारण समिति बनाई है। यह समिति परीक्षा केंद्र से रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज सहित समय की बर्बादी के डिटेल्स पर गौर करेगी। पूरे देश में इस परीक्षा की पारदर्शिता से समझौता नहीं किया गया। कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पूरी परीक्षा प्रक्रिया बहुत पारदर्शी रही।

गौरतलब है कि नीट में 67 छात्रों के 720 में से 720 अंक पाने और कटऑफ के अचानक आसमान छूने के बाद हजारों छात्र, पेरेंट्स और कोचिंग संचालक पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने भी नीट मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग कर डाली है। पिछले दिनों दी गई एनटीए की सफाई उन्हें तार्किक नहीं लग रही है।

बहुत से नीट अभ्यर्थियों का आरोप है कि नीट का पेपर लीक होने की वजह से रैंक और नंबर को बुरी तरह प्रभावित किया है। पेपर लीक होने की वजह से रैंक में इनफ्लेशन हुआ है। सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी नीट स्कैम, नीट परीक्षा रद्द करो और नीट रिजल्ट फिर से जारी करो हैश टैग से लगातार अभियान चला रहे हैं। एनटीए का कहना है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और ग्रेस मार्क्स देने की वजह से टॉपरों की संख्या बढ़ गई है।

क्यों हो रहा हंगामा, छात्र लगातार पूछे रहे ये सवाल

1. एक ही एग्जाम सेंटर से छह टॉपर कैसे हो सकते हैं ? बहुत से स्टूडेंट्स का कहना है कि एनटीए ने नीट टॉपरों की जो मेरिट लिस्ट जारी की है उसमें 8 स्टूडेंट्स के रोल नंबर एक ही सीरीज के हैं। सीरियर नंबर 62 से लेकर 69 के तक के 8 स्टूडेंट्स में से 6 स्टूडेंट्स रैंक 1 पाने वाले टॉपर हैं। आठ में से छह हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित एक ही एग्जाम सेंटर के हैं। सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी व एग्जाम एक्सपर्ट्स ने इसे लेकर नीट की पारदर्शिता पर संदेह जताया है। 8 में से 7 स्टूडेंट्स का सरनेम लिस्ट में क्यों नहीं लिखा है? इन स्टूडेंट्स का नीट रोल नंबर, नाम, मार्क्स और रैंक को हाईलाइट करने वाला स्नैपशॉट सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। इन 8 में से 6 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 अंक मिले हैं। अन्य दो को 719, 718 हैं। एनटीए ने इस पर सफाई में कुछ दिन पहले कहा कि हरियाणा के एग्जाम सेंटर पर स्टूडेंट्स का समय बर्बाद हुआ था, इसके चलते उन्हें मुआवजे के तौर पर ग्रेस मार्क्स दिए गए।
2. छात्र, पेरेंट्स व कोचिंग संचालकों ने पूछा है कि एनटीए बताए कितने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिले हैं? किसे कितने कितने मार्क्स दिए गए हैं? बिना ग्रेस मार्क्स के भी नीट की ऑरिजनल मेरिट लिस्ट जारी होनी चाहिए।
3. ग्रेस मार्क्स को लेकर एनटीए ने नोटिफिकेशन में कोई जानकारी नहीं दी थी। फिर अचानक रिजल्ट में इस पॉलिसी को क्यों किस आधार पर लागू किया गया?
4. किन सेंटरों पर टाइम लॉस हुआ है और किस आधार पर इन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं।
5. एनटीए नॉर्मलाइजेशन पर स्पष्टीकरण दे। इसका क्या फॉर्मूला रहा। किस आधार पर यह दिया गया।
6. कितने सेंटरों के स्टूडेंट्स पर नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया।
7. 718 और 719 मार्क्स कैसे आए, जबकि यह असंभव है। इन स्टूडेंट्स ने तर्क दिया कि नीट का पेपर 720 नंबर का होता है। हर सवाल चार नंबर का होता और गलत उत्तर पर एक अंक की नेगेटिव मार्किंग होती है। कोई छात्र अगर सभी सवाल सही करता है तो उसके पूरे 720 में से 720 आते हैं और अगर एक सवाल छोड़ देता है तो उसके 716 अंक आएंगे। वहीं एक सवाल गलत करता है तो उसके 715 अंक रह जाएंगे। ऐसे में 718 व 719 अंक हासिल कर पाना असंभव हैं। 720 के बाद किसी के 715 और 716 अंक ही आ सकते हैं।
8. नीट की टाइ ब्रेकिंग पॉलिसी रिजल्ट के समय क्यों बदली गई है। 8वां नियम क्यों डाला गया है जबकि नोटिफिकेशन में इसका कोई जिक्र नहीं था, केवल 7 पैरामीटर ही थे? पहले आवेदन करने वाले को मेरिट में ऊपर रखा जाएगा, यह पहले क्यों नहीं बताया गया।
9. कितने टाइम लॉस होने पर कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं?
10. लोकसभा चुनाव परिणाम के दिन ही नीट रिजल्ट क्यों जारी किया गया? जबकि इसकी संभावित तिथि 10 दिन बाद थी।

साप्ताहिक समय माया

केंद्र व राज्य शासन के सभी शासकीय विभाग सूचना के अधिकार की बिखेरते रहें धज्जियां

शासकीय, व्यवसायिक, निजी सारी बातचीत जानकारियां संग्रहित हैं स्मार्टवाच एंड्रॉयड में

कितना भी छुपाइए बचाइए दबाइये, झूठ, छल, कपट करिए पर अन बोला कहा सच भी हो सकता है सार्वजनिक

देश और दुनिया में आधुनिकता के साथ जिस प्रकार से पहले 2जी फिर 3जी, 4जी और अब 5जी मोबाइल एंड्राइड और स्मार्ट वॉच स्मार्ट टीवी जिसका आप हम सब उपयोग कर रहे हैं। यथार्थ में यह आधुनिकता नहीं आधुनिकता का अभिशाप है। जो आपके 5जी के साथसोने के विचारों को भी पकड़ कर सार्वजनिक कर सकता है भले ही आपने उन विचारों को मुंह से उच्चारित कर शब्दों से बात की या कहीं नहीं भी बोला या उपयोग न भी किया हो तो भी वह आपकी मस्तिष्क की तरंगों को संग्रहित कर विश्लेषित कर अंदाज लगा कर आपकी सोच के अनुकूल आपके मोबाइल कंप्यूटर पर इंटरनेट ऑन करते ही उसके विज्ञापन आने शुरू हो जाते हैं जो स्पष्ट करते हैं कि आपकी मस्जिद की तरंगों का भी स्मार्ट वॉच, एंड्रॉयड फोन, या घर में लगा स्मार्ट टीवी आपका परिवार के सदस्यों की उपयोग न करने या बंद रहने पर भी दशावली को रिकॉर्ड कर सीधे कंपनियों को भेज कर सीधे ही उपयोग कर अपने लाभ की गणना कर लेते हैं और उसी हिसाब से आपको मोबाइल पर इंटरनेट चालू होने पर विज्ञापन या संबंधित विषय की जानकारी उपलब्ध करवाने लगते हैं। जो मेरे सच को स्पष्ट करता है।

साथी यह जानकारी न केवल गूगल माइक्रोसॉफ्ट वरन चीन के साथ भारत की सरकार भी विशेष परिस्थितियों में संग्रहित कर रही है। आपने देखा किस प्रकार से चीनी लोन एप्स आसानी से लोन देकर पर कई गुना ज्यादा ब्याज वसूल करने के लिए आपका फोन नंबर के सारे डेटा सारे वीडियो सारी संपर्क सूची गोवा आसानी से एकत्र कर कर्ज लेने वाले के मोबाइल की संपर्क सूची वालों को आपके ही मोबाइल से निकाल अश्लील चित्रों भाषा गाली गलौज कर नाथ और वसूली के अनेकों किस्से सामने आए, अखबारों में छपे इन सबसे परेशान होकर देश व प्रदेश में ही अनेकों परिवारों को बदनामी के कारण सामूहिक आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ा। इसलिए एंड्रॉयड फोन को कभी भी खुले में ना रखें।

स्मार्ट वॉच जिसको पहनकर अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं। कभी भी उपयोग न करें क्योंकि यह आपके हाल-चाल से लेकर सांसों तक की गिनती करता है। घर के स्क्रीन टीवी पर चलते समय या बंद होने पर भी यह आपकी रिकॉर्डिंग करता है। इसलिए उस कमरे में टीवी के सामने कोई भी अश्लील वार्तालाप न करें। उपयोग होने के बाद उस पर मोटा काला कपड़ा ढांक दें। शयनकक्ष में स्मार्ट टीवी ना लगायें। ताकि आपकी गोपनीयता या अन्य कृत्य कभी सार्वजनिक ना हों।

केंद्र वा राज्य सरकारों के सरकारी मंत्रालयों से लेकर सभी विभागों कार्यालयों से गांवों की पंचायतों तक सूचना का अधिकार अधिनियम 05 की धारा 4 के अंतर्गत 19 साल के बाद में भी 25 बिंदुओं की जानकारी अपने भ्रष्टाचार जालसाजियों लूट खसोंट को छुपाने दवाने के लिए बड़े ही मंत्रालय ना भी कर रहे हों। परंतु सूचना के अधिकार में आवेदन देने पर अधिकांश विभागों के कर्मचारी अधिकारी पहले तो आवेदन ही नहीं लेते और अगर आवेदन ले भी लेते हैं तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय आदि के निर्णय की कॉपी लगाकर जानकारी देने से बचते और छल कपट कर भले ही आवेदकों की मजाक उड़ाते और कानून की धज्जियां बिखेर अपनी बहादुरी का डंका पीट बचाते छुपाते हों। परंतु उनका सारा सच क्षण भर में उनकी स्मार्ट वॉच और एंड्रयड मोबाइल फोन से न केवल जांच एजेंसियों के साथ हैकरों को भी एक झटके में आसानी से मिल जाता है।

शासकीय विभागों में बैठे इंजीनियर डॉक्टर अधिकारी कर्मचारी यह न समझ लें कि उन्होंने भ्रष्टाचार करके सूचना के अधिकार में जानकारी नहीं दी। तो वे बच जाएंगे। उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं लेगा। बंधी हुई स्मार्ट वॉच और उपयोग किया जा रहे एंड्राइड व अन्य प्रकार के मोबाइल आपकी हर हरकत बातचीत काम धाम, घूमना फिरना, उठना बैठना, लोगों से मिलने जुलने का न केवल रिकॉर्ड कर रहे हैं वरन 10 साल बाद भी आपकी सारे कुकर्मो भ्रष्टाचारों जालसाजियों की सच्चाइयों को सरकार को हैकर को लोकायुक्त सीबीआई इओडब्ल्यू एस आई टी आदि जांच एजेंसियों को आसानी से सारे रिकॉर्ड मिल सकते हैं।आप भले ही सूचना के अधिकार में आवेदकों के मजाक उड़ाते रहे जानकारी देने से बहाने बाजी नौटंकी हरामखोरी जालसाजी कर जानकारी देने से बचते रहें। तो यह मत समझ लेना कि आप बड़े आराम से भ्रष्टाचार करके बचे रहेंगे। बेशक आपके संरक्षक वरिष्ठ अधिकारियों नेताओं मंत्रियों को आपको महीना रॉयल्टी कमीशन देना पड़ता है।

उसी के संरक्षण और दम पर आप सारे भ्रष्टाचार जालसाजिया कर पाते हैं। जो भौतिक दुनिया आपको दिख रही है। इसके पीछे अनेकों प्राकृतिक दुआओं बददुआओं की अदृश्य शक्तियां, मष्तिस्क की तरंगें भी काम कर रही हैं। बड़े-बड़े दिग्गजों को धूल में मिलते या शरीर त्यागते क्षण भर नहीं लगता है। तो गुंडागर्दी अकड़ दादागिरी सब मिट्टी में मिल जाती है। फिर अपनी भी जवान काली ही है। जब दुनिया पर कोरोना का भारी संकट आया तब अकेला ही सबको बचाने के लिए लड़ रहा था और प्रभु के आशीर्वाद से 2 महीने में मध्य प्रदेश खुलवा लिया था। 6 महीने में देश और दुनिया दो ढाई साल तक नहीं खुल पाई थी। फिर पिछले 20 सालों से अकेले ही विश्व घातक संगठन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सारी दुनिया के व्यवसाय पर कब्जा करने के षड्यंत्र के खिलाफ किसानों मजदूरों दुकानदारों बाजारों मंडियों को बचाने का युद्ध अकेले कर ही रहा हूं। और प्रभु के आशीर्वाद से सबको बचाए रखने में अभी तक सफल रहा हूं। जबकि देश दुनिया का मीडिया मेरा व उन किसानों मजदूरों छोटे दुकानदारों व्यवसाय एवं उद्योगों को बचाने में साथ नहीं दे रहा।

तो प्रकृति ने इतनी क्षमताएं तो दी है की भ्रष्टों जालसाजों छल कपट करने वालों को दृश्य व अदृश्य तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त समुचित प्रति उत्तर दिया जा सके। इसको समझें। सहयोग दें व पीड़ाओ का समन करें। किसी को भी होशियारी चालबाजी दिखा पीड़ित कर पीड़ित होने से बचें।

अकाल शयन शैय्या पर अल्प, दीर्घ या सदा के लियें विश्राम तो निश्चित ही है। पूरा विश्व एक दूसरे के सहयोग से ही चलता है। स्वयंभू बनना किसी की औकात नहीं। इसे सदा याद रखें। वक्त सदा सगा मंत्री प्रधानमंत्री से लेकर बड़े-बड़े पूंजीपति माफियाओं सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों व्यवसायियों से लेकर नेताओं मंत्रियों गुंडे बदमाशों का भी व कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जीवन में उतार चढ़ाव आनास्वाभाविक प्रक्रिया है। पर आपकी ज्यादीतियां अपराध झूठ छल कपट जिनका अपने सहयोगियों से लेकर पीडितों तक मैं अपने कलाई पर जो स्मार्ट वॉच और एंड्रॉयड फोन का उपयोग कर रहे हैं यह सब आपके हर कृत्य लेन-देन, बातचीत को अच्छा है तो अच्छा और बुरा है तो बुरा सब दर्ज करआपके जीवन का सच क्षण मात्र में भी सार्वजनिक करने में सक्षम है। जो तकनीकी आपकी सुविधा के लिए बनाई गई थी। वहअति प्रयोग से आपके लिए अभिशाप बनती जा रही है यह सभी स्तर के व्यक्ति याद रखें। हमारा धरती पर जन्म नग्न खाली हाथ हुआ है।

तो मृत्यु भी निश्चित खाली हाथ जाने के लिए ही है। तो बेहतर होगा कि इन तकनीकीयों का उपयोगकर हम सब एक दूसरे को सहयोग कर बेहतर और सुखद भविष्य के लिए उपयोग करें। बेशकपृथ्वी पर जन्म लिए हर प्राणी को प्रकृति ने उसके जीवन के लिये अनुकूल क्षमतायें शक्तियां कष्ट सुविधायें दी हैं। हम ना कर्ता है ना कारक हैं। केवल माध्यम की भूमिका निभा रहे हैं। तो जो कंपनियां सरकारें हैकर्स स्मार्ट वॉच और एंड्रॉयड फोन से दुनिया के 400 करोड लोगों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर भी रही है। तो भी मन का धन कर लें। बाकी कुछ ज्यादा उखाड़ बिगाड़ किसी की नियति से ज्यादा नहीं कर सकतीं।

साप्ताहिक
समय माया
samaymaya.com

करोड़ों किसानों मजदूरों छोटे व्यवसायियों
उद्योगों, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों
ठेका संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा व देशी
विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के षड्यंत्रों के
विरुद्ध पिछले 25 वर्षों से संघर्षरत

साप्ताहिक समयमाया समाचार पत्र व
samaymaya.com की वेबसाइट पर
समाचार, शिकायतें और विज्ञापन
(प्रिंट एवं वीडियो) के लिए संपर्क करें

मप्र के समस्त जिलों में एजेंसी देना है
एवं संवाददाता नियुक्त करना है

मो. 9425125569 / 9479535569

ईमेल: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
संपादकः अजमेरा एस.पी. कुमार, मो. 9425125569, भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958